RAJYA SABHA

Wednesday, the 1st December, 1999/10 Agrahayana, 1921 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Powerloom, Handloom and Handicrafts units in Gujarat

*41. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of powerloom, handloom and handicrafts units functioning at present in different parts of Gujarat and the employees engaged in each of them;

(b) whether it is a fact that some of the units are running in losses;

(c) if so, the details thereof, unit-wise, and the reasons therefor; and

(d) the effective measures being taken or proposed to be taken by Government to give financial assistance and other incentives to revive these sick units in the State?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The information available in this regard is as below:

	No. of Units	Employees engaged
Powerloom	31317	770000
Handloom	16340	57936
Handicrafts	32697	141970

(b) and (c) At a given point of time, in any industry, there would be units running in losses due to a variety of reasons such as demand recession in domestic and international market, technological

obsolescence and financial problems. It is not possible to compile the unitwise details because of the decentralised nature of the industry.

(d) The Government has launched the Technological Upgradation Fund Scheme (TUFS) for the Textile and Jute Industries which is in operation since 01.4.99 for 5 years i.e. upto 31.3.2004. Besides, the Central Government provides support to these sectors through various schemes including welfare schemes for those engaged in these sectors some of these schemes are as follows:

Sector	Schemes
Powerloom	i) Powerloom Service Centres
	ii) Computer Aided Design Centres
	iii) Group Insurance Scheme for Powerloom Workers
Handloom	i) Project Package Scheme
	ii) Handloom Development Centre and Quality Dyeing Unit Scheme
	iii) Health Package Scheme
	iv) Thrift Fund Scheme
	v) Market Development Assistance Scheme
Handicrafts	i) Training Schemes
	ii) Design and Technical Developments
	iii) Marketing and Market Development Support
	iv) Craft Development Centres
	v) Workshec-cum-Housing Scheme

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस हाउस में पहले जो अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि 1.4.99 से टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन के लिए नई स्कीम ला रहे हैं इसके लिए मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने सभी बातें अब लागू की हैं। मेरा सवाल सिर्फ गुजरात के बारे में है और मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने जो

कुछ पैकेंज और स्कीम्स बनाई है उनसे गुजरात के लोगों को कितना लाभ हुआ है? यहां अन्य राज्यों का सवाल नहीं है केवल गुजरात में कितने लोगों को फायदा हुआ है तथा कितनी योजना लागू करनी बाकी है, यह बता दें?

श्री काशीराम राणाः सर, वैसे तो मैंने अपने जवाब में ही कहा है कि पावरलूम, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स में इम्पलाइज इस प्रकार हैंः पावरलूम में 770000 हैं, हैंडलूम में 57936 हैं और हैंडीक्राफ्ट्स में 141970 हैं। सर, जैसे हम देशभर में बहुत सारी योजनाएं इम्पलीमेंट करते हैं उसी प्रकार से गुजरात में भी इम्पलीमेंट की हैं। जहां तक गुजरात में हैंडलूम का सवाल है, जो राज्य सरकारों ने डिमांड की है उसी डिमांड के आधार पर हम राज्य सरकार को मदद करते हैं, जैसे पीपीएस प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम है, हैंडलूम की हेल्प पैकेज स्कीम है, गुजरात सरकार ने 1998-99, 1999-2000 में कुछ मांगा नहीं है इसलिए नहीं दी गई। वैसे ही थ्रिफ्ट फंड है, न्यू इंश्योरेंस है, एमडीए है। गुजरात सरकार से हमारे पास जो प्रोपोजल आई है इसके आधार पर हमने वहां मदद की है। हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए जैसी दिल्ली में अर्बन हाट है वैसा ही अहमदाबाद में अर्बट हाट बनाया जाएगा। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश के सभी राज्यों में ऐसे हाट बनाए जाएंगे। गत वर्ष ऐसे पांच हाट बनाए गए थे। इस साल की हमारी स्कीम में अहमदाबाद में इसे बनाने की स्कीम है। हमारे हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन को हैंडीक्राफ्ट की सुविधा के लिए मार्किटिंग सैंटर की स्कीम भी बनाई है जो सूरत में सैट-अप होने जा रही है।

श्री अनन्तराय देवशंकर द्वेः मंत्री जी ने कहा है कि गुजरात सरकार ने प्रोपोजल नहीं भेजी है लेकिन मैंने पिछले साल भी यह सवाल यहां उठाया था। जैसा अभी उड़ीसा में साईक्लोन आया है वैसा साईक्लोन कच्छ और सौराष्ट्र में विन्टर समर साईक्लोन दो साल से चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार के जरिए जो स्केयरसिटी वाले एरियाज हैं कच्छ और सौराष्ट्र, पार्टिकुलरली कच्छ, वहां हैंडीक्राफ्ट्स का काम दुनियाभर में मशहूर है। तो क्या गुजरात सरकार के जरिये केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई पैकेज बनाकर वहां के लोगों को हैंडीक्राफ्ट का काम दे रही है जिससे वहां अभी जो स्केयरसिटी है, लोगों के पास काम नहीं है तो उन लोगों को, गरीब लोगों को काम मिल सके और घर में बैठकर महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का मशहूर काम कर सकें और उनको रोजी-रोटी मिले? क्या सरकार इस बारे में सोचकर कोई कदम उठाएगी?

श्री काशीराम राणाः सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए, जहां पर स्केयरसिटी है या जहां पर साइक्लोन आया, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार की ओर से जो डिमाण्ड आती है वह हम फुलफिल करते हैं। जैसे केरल साइक्लोन को मेंशन किया गया। जो हमारी प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम है उसमें से 1997-98 सिर्फ 3.6 लाख रुपया दिया गया था, 1998-99 में करीब 11 लाख रुपया पी॰पी॰एस॰ के अंतर्गत दिया गया था। यदि ऐसी कोई स्केयरसिटी या कोई साइक्लोन इफेक्टड एरिया है तो वहां

हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के बारे में स्टेट गवर्नमेंट हमें सिफारिश करती है तो हम उसे प्रायोरिटी में अवश्य लेते हैं और इसके आधार पर स्कीम मंजूर करते हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि यदि ऐसी कोई स्कीम आती है तो सरकार उसके प्रति अवश्य ध्यान देगी।

MR. CHAIRMAN: Dr. Radhakrishna Murthy. This question relates to Gujarat only.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTHY: There is an expert committee on textiles, whose report was submitted last June-July, and this mentions about the entire country, including Gujarat. That is why I am putting this question. I would like to know whether the Government has examined the Expert Committee Report on Textiles Policy, which is commonly called the Satyam Committee Report. I would also like to know the reaction of the Government to it. Has the Government examined these proposals and what is the Government's thinking on this Report? Sir, if the Minister wants to know some of the salient points, I can supply the same.

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, the Government has appointed the Expert Committee under the Chairmanship of Mr. Satyam. The Satyam Committee has already submitted its report to the Government, as the hon. member has stated. All recommendations given by the Satyam Committee are under the active consideration of the Government. But, no final decision has been taken till now. Nowadays, Sir, we examine not only the Ministries of Labour and Finance, but we also try to get the opinion of the various other concerned Ministries. It is only after that that we will finalise the new Textiles Policy.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, the powerloom and handloom industries are getting more and more sick because of the bufferstocks which come from abroad and which are sold at cheaper rates. As a result, I don't think that there would be any question of survival so far as our handloom and powerloom industries are concerned. Is there any view or policy with the Government to make them survive through certain subsidies?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, so far as the powerloom and handloom industries are concerned, the Government is confident that the deteriorating position of these two sectors will be certainly checked, and they will be revived. The Government is taking a lot of steps in this regard. Just for instance, in case of powerlooms, we have

launched the Technology Upgradation Fund Scheme. We are also going to launch the Cotton Technology Mission. We are also going to frame a new textile policy. So far as subsidy is concerned, for example, in the case of handlooms, we are giving so much financial assistance under the project package scheme, the insurance scheme, the health scheme and so many other schemes. We are also giving some financial assistance to the employees, the weavers and the artisans.

श्री मोहम्मद सलीम: सर, गुजरात में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के बारे में हमारी एक विरासत है, कुछ परम्परायें हैं। लेकिन ऐसे बहुत से ट्रेडीशनल फार्म्स आफ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो था आज उसकी स्किल कम हो रही है। गुजरात के बारे मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं कि आपने जो यहां स्कीम बताई है टेक्नीकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम, यह होल कन्ट्री के लिए है जब कि सवाल यह था कि गुजरात में जो सिक हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और पावरलूम यूनिट्स हैं उनको आपने क्या सहायता प्रदान की है। इसको इसमें गुजरात के बारे में क्वांटिफाई नहीं किया गया है। अगर ओरिजनल सवाल आप देखें तो इसमें है कि इस राज्य में इन रुग्ण इकाईयों का पुनरुद्धार करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं अथवा किये जाने का विचार है?

मंत्री महोदय का आंसर अगर देखेंगे जो डी में है, वह आंसर जनरल है इन मंत्री महोदय से पहले जो कई दूसरे मंत्री थे उनका भी इसी तरह का आंसर होता था कि हमारे पास इसके लिए स्कीम्स हैं, the Government has launched the Technology Upgradation Fund, और यह एक, दो तीन करके है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो इसकी नोडल एजेंसी है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उसमें भ्रष्टाचार है और जो रियल आर्टिजन हैं, जो हैंडलूम वीवर्स हैं उनके बजाए जो पावर लूम के लोग हैं वे उनको घेरे रहते हैं। वर्षों से ये अर्टिजन और हैंडलूम वीवर्स, जिनके पास ओरिजनल स्किल हैं, परम्परागत रूप से है वे उनसे सहायता मांगते हैं और खासकरके अगर वे मार्केटिंग असिस्टेंस मांगते हैं तो उनको देने के बजाए जो शोरुम वाले हैं उनको सहायता देते हैं। ऐसे जितने भी सेंटर खुलते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए गुजरात के संदर्भ में अगर आप इनको क्वांटिफाई करके हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स को सहायता दें तो यह ज्यादा उचित होगा। लेकिन अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे तो उनकी स्थिति वही रहेगी जो है।

श्री काशीराम राणा: सर, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि गुजरात में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम तथा पावरलूम में बड़ा स्कोप है। सर मैं यहां पर एक बात अवश्य बताऊंगा, आगस्ट हाउस में कि हैंडलूम की जो प्रोडक्टिविटी फार लूम है, उसमें हमारा नेशनल एवरेज जो है वह 2.36 है

Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the Debate.

जब कि गुजरात का 9.38 है और प्रोडक्टिविटी फार वीवर्स इन हाउस होल्ड यूनिट उसका नेशनल ऐवरेज 3.66 है जब कि गुजरात का 10.17 है। इसको देखते हुए हैंडलूम और बढ़ना चाहिए। लेकिन गुजरात में हैंडलूम कम होता जा रहा है। वहां हैंडलूम में जितनी स्कीमें बनी हुई हैं उनको पावरलूम ले लेता है। इसके कारण पावरलूम की संख्या बढ़ जाती है और हैंडलूम की संख्या कम होती जा रही है। अभी गुजरात में 16340 यूनिट्स हैं जो पहले से कम है लेकिन पावरलूम्स की संख्या बहुत बढ़ गई है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार की बताई। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो आर्टिजन और वीवर्स हैं उनके प्रोडक्शन को सीधे बायर्स तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं। इस बारे में मैंने जैसे पहले बताया आर्टिजन हाट की हर स्टेट में व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वे अपना प्रोडक्ट मार्केट में सीधा लाकर उसको बेच सकें। ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार हर स्टेट में मार्केटिंग कम्पलेक्स भी बनाने जा रही है ताकि भ्रष्टाचार कम हो। करप्शन दूर करने के लिए और भी स्टेप हमने लियें हैं क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं उनको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी अकाऊंटेबिलिटी अच्छी नहीं है और उनका पास्ट रिकार्ड भी अच्छा नहीं है। यह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का हमारा पैसा और सारी हैंडलूम की स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलती हैं, उसमें राज्य सरकारों को भी अपना शेयर देना पड़ता है। कई राज्यों की सरकारें अपना शेयर नहीं दे पाती हैं जैसे नागालैंड है, नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर हमारे सारे फंड का यूटीलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। चूंकि स्टेट्स को अपना शेयर देना होता है इसलिए स्टेट्स प्रोपोज़ल या रिक्मेंडेशंस नहीं भेजती हैं। लेकिन इसका भी कोई रास्ता निकाल कर हम सीधे उनको पैसा दे सकें, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं।

Power Shortage

42. SHRI JALALUDIN ANSARI[1]
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the over all shortage of power; and

(b) what steps are being taken to meet this shortage?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM) (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The overall energy shortage in the country during April to October 1999 was 4.8% compared to energy shortage of 5.3% in the corresponding period last year, and a shortage of 8.1% in 1997-98.

[1] The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Jalaludin Ansari.